IAS Mentorship

Reyasat Ali sir & Experienced team in CSE prep

CSE Main 2023: Mini Mock Test 8

Syllabus:	• • **Indian Economy (10 Qs)** • •	
Name of Candidate	MOHAN MANGAWA	
Email Id		
Date		Medium: Hindi / English
Time: 1 Hour & 30 Mints	Start Time:	End Time:

Q. No.	Max. Marks	Marks obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	15	
7	15	
8	15	
9	15	
10	15	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Total	125	
Invigilator	Signature	

WhatsApp/Telegram/Text/Call: 8090528260

Scanned with OKEN Scanner

	Excellent	Good	Average	Unsatisfied
Introduction				
Conceptual Understanding				
Contextual Clarity				
Content Enrichment				
Presentation				
Alignment				
Contextual Justification				

Scanned with OKEN Scanner

Q1. Examine the potential of Small and Medium Scale enterprises (SMEs) as a key driver of economic growth and employment generation in the country in present time. 150 words

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लघु एवं मध्यम उद्योग की ~36 मिलियन इकाईयाँ कार्यरत हैं जो 110M रोजगार प्रदान कर रही हैं।

MSMEs की क्षमता

→ GDP में बड़ा योगदान → 6.11%

→ छोटे उद्योगों द्वारा विनिर्माण क्षेत्र का विकास → GDP का ~24%

→ वित्तीय समावेशन व सेवा प्रदाता उद्योग रूप में भी पहचान

→ स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा

→ प्रशांतस्करण इकाईयों के रूप में

→ ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थिति → डिवाइड को पाटने में मदद

प्रयासों की राह

- बेहतर क्लियरिंग इकोसिस्टम
  - ↳ EoDB
  - ↳ सिंगल विंडो व्यवस्था
- फंडिंग हेतु पर्याप्त मैकेनिज्म की जरूरत
- बैंकिंग व अन्य बीमा आदि सुविधाओं हेतु प्रावधान जरूरत
- क्लस्टर्ड एप्रोच को अपनाना जरूरी
  - ↓ वृहत विनिर्माण हेतु

किए गए प्रयास

- → यू.के. सिन्हा समिति की सिफारिश पर परिभाषा परिवर्तन
- → RAMP, ASPIRE, Zero Effect Zero Defect जैसी स्कीम्स
- → ~~प्रोत्साहन~~ प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (PLI) & डिजाइन लिंक्ड स्कीम से जोड़ना।

इस प्रकार बढ़ते वैश्विक निर्माता के रूप में भारत को अपने स्थानीय स्तर उद्योगों को और अधिक वित्तीय सहायता व तकनीकी पहुंच प्रदान करने की जरूरत है।

Q2. Critically examine the significance of the National Green Hydrogen mission. 150words

ग्रीन हाइड्रोजन से तात्पर्य हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग करके ग्रीन ऊर्जा द्वारा किया गया हो।

$$H_2O \xrightarrow[\text{विद्युत}]{\text{ग्रीन}} H_2 + O_2$$

NGHM का महत्व

- ऊर्जा सुरक्षा → 2030 तक 125 GW हरित जोड़ने की योजना
- पर्यावरणीय → कार्बन फुटप्रिंट में कमी
  - संधारणीय व जलवायु अनुकूल
- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में बड़ी क्षमता (2030 तक 500GW का लक्ष्य)
- तकनीकी विकास → रिमोट क्षेत्रों में उत्पादन इकाईयाँ

समस्याएं

- उच्च उत्पादन लागत
- आवश्यक तकनीकी की कमी
- बेहतर क्षेत्र पहचान की कमी तक नहीं
- स्टोरेज क्षमता की कमी
  - अत्यधिक ज्वलनशील

जरूरत

- क्षेत्रों का चयन क्षमता आधार पर
  - मुख्यतः पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्र
- निजी क्षेत्र निवेश को आमंत्रण
- तकनीकी हस्तक्षेप → निम्न लागत उत्पादन प्रणाली
- ग्रीन इकॉनोमी को चक्रीय बनाना

वाहन → ग्रीन ऊर्जा → ग्रीन हाइड्रोजन → वाहन

इस प्रकार भविष्य की इस तकनीकी व ऊर्जा स्रोत पर प्रारंभिक प्रयासों की जरूरत है जो SDG लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होंगे।

Q3. Introduction of technology in agriculture should be environmentally and socially sustainable. Analyse the statement in the context of GM crops in India. 150 words

हाल ही में GEAC द्वारा GM सरसों को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई लेकिन इसके संधारणीयता पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं—

तकनीकी की पर्यावरणीय/सामाजिक संधारणीयता

↳ जैव-विविधता की रक्षा हेतु जरूरी उदा० DMH-11 सरसों परागण के कारण नुकसान पहुँचा सकती है।

↳ सुपरवीड्स व प्रतिरोधी खरपतवार का निर्माण नहीं होने देना ⇒ GM के पास के साथ हो रहा है।

↳ पर्यावरणीय अनुकूलित व जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी ⇒ सूखा, अधिक तापमान

↳ पोषक तत्वों की पूर्ति ⇒ गोल्डन राइस Vit A
↳ खाद्य सुरक्षा हेतु

↳ उत्पादकता में बढ़ोतरी ⇒ भारत का विश्व में आयातक से निर्यातक (4th स्थान)

परन्तु चुनौतियाँ →
- एक समय के बाद उत्पादन गिरावट
- कीट-पतंगों व खरपतवार द्वारा प्रतिरोधकता
- टर्मिनेटर बीज के कारण MNCs की मोनोपॉली
- स्वास्थ्य व नैतिकता संबंधी पर्यावरण मुद्दे

अतः आवश्यकता →
- GEAC को वैधानिकता व फण्ड्स ढाँचा बढ़ाना
- विभिन्न हितधारकों → किसान, सरकार, सिविल सोसायटी की सहमति

↳ GM फसलों को सामान्य फसलों से अलग रखना

↳ FSSAI द्वारा विभिन्न मानक व उचित मानकीकरण पर जोर

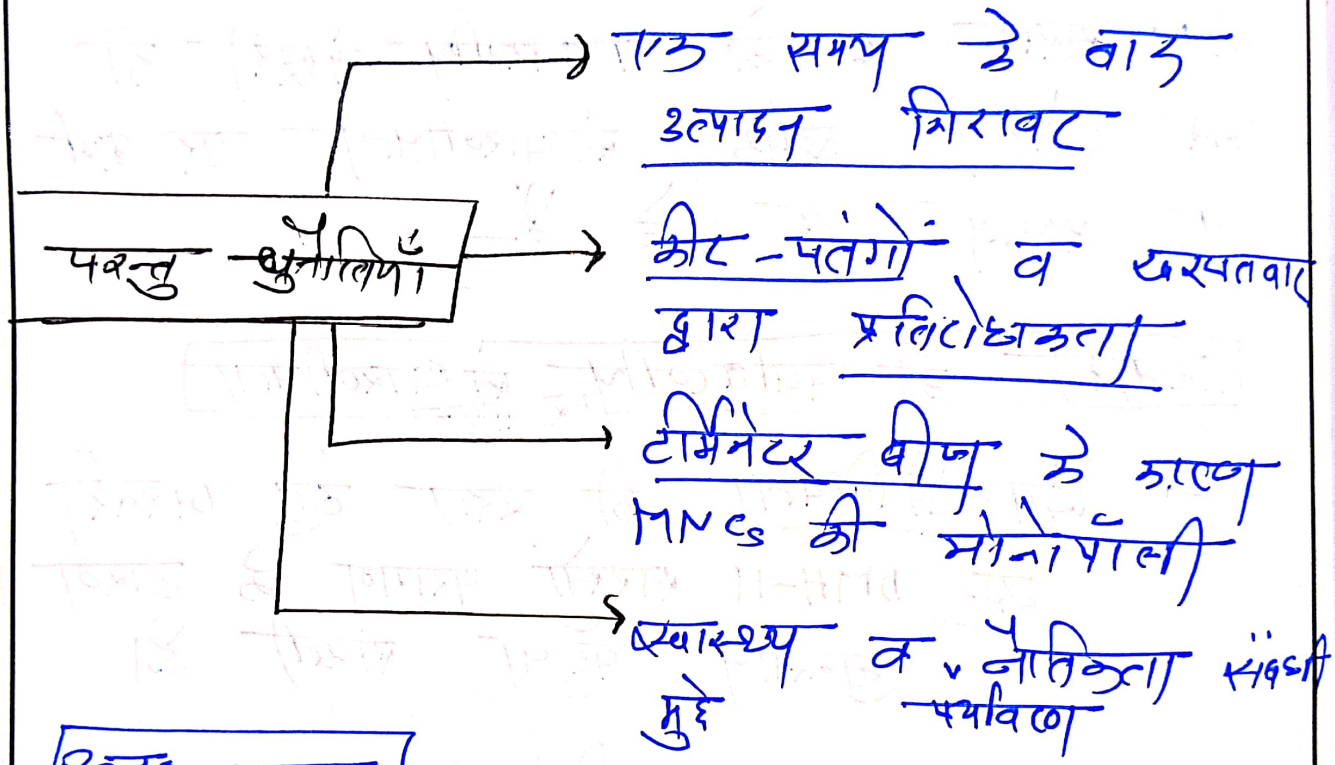

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q4. The practice of livestock rearing is an old aged practice; however, its significance has multiplied in the recent times. Comment 150 words

हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन जनसंख्या 2021-22 के अनुसार भारत में कुल पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि न केवल जैव विविधता बल्कि सामाजिक - आर्थिक भूमिका निभा रहा है।

पशुधन पालन महत्व

- सामाजिक
  - सामाजिक पहचान का प्रतीक
  - पारिवारिक खाद्य जरूरतों की पूर्ति
  - खेती आदि कार्यों में काम आना
- आर्थिक
  - चलता - फिरता बैंक [कभी भी बेचकर धन प्राप्ति]
  - दुग्ध उत्पादन, अंडे, मांस आदि द्वारा आर्थिक लाभ

NABARD 16% कुल आय

पर्यावरणीय → खाद प्राप्ति → केंचुए व अन्य पशुओं से
→ ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु जीवामृत-बीजामृत आदि पूर्ति
→ जलवायु परिवर्तन व कृषि उत्पादकता में कमी के समय महत्वपूर्ण

समस्याएं

- कम कृषि उत्पादकता → चारा उपलब्धता कमी → 67% महंगा
- उच्च तापमान के कारण हीट सेंसिटिविटी स्ट्रोक → उत्पादन कमी
- कृषि का मशीनीकरण
- सहकारी समितियों का स्पष्ट प्रदर्शन

जरूरत → बेहतर नीति निर्माण → राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोपाला ऐप
→ मत्स्यपालन, मुर्गीपालन आदि हेतु सब्सिडी
→ उन्नत व फूड आदि में नवाचार व कम कीमत उपलब्धता

इस प्रकार किसान जीवन का आधार पशुधन हेतु बेहतर नीति-प्रयोग आय दोगुना करने में सहायक होंगे।

. Capitalism has guided the world economy to unprecedented prosperity. However, it has also ıtributed to wide disparities between rich and poor as highlighted by Oxfam report. Highlight ıer causes of this disparity. 150 words

ऑक्सफेम की 'Inequality Virus & Inequality kills' रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में पूंजीपतियों की आय में 3x वृद्धि हुई जबकि गरीबी में 2x वृद्धि।

पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा उत्पन्न परिणाम

सकारात्मक

- बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा → गुणवत्ता ↑
- नवाचार व शोध आदि को प्रोत्साहन
- क्षमता आधारित संसाधन प्राप्ति पर बल
- राज्य का कम से कम हस्तक्षेप → मांग-आपूर्ति द्वारा संचालन

नकारात्मक

- संसाधन असमान वितरण
- गरीब - अमीर की खाई बढ़ी हुई
- लोककल्याणकारी अवधारणा का पीछे छूटना
- केवल लाभ आधारित ↳ पर्यावरण, समाज ↓

Scanned with OKEN Scanner

असमानता के कारण

सामाजिक
- गरीबी में जीवन की प्रवृत्ति
- स्वास्थ्य-शिक्षा तक पहुँच नहीं
- भू-सुधार असफलता व लोककल्याण योजना तक पहुँच नहीं

आर्थिक
- कुपोषण व कौशलाभाव [5% कौशल मात्र किल]
- आर्थिक क्षेत्रों के बीच व्यापक असमानता
  - कृषि मजदूर 400₹/Day जबकि कॉर्पोरेट CEO 20000₹/Day [C&Y सर्वे]
- कृषि क्षेत्र में अधिक जनसंख्या लेकिन CAGR 3.4% मात्र
- बढ़ता शहरीकरण, जनसंख्या दबाव व जलवायु परिवर्तन → कोरोना आदि

आगे की राह → समावेशी विकास प्रोच ⇒ लोककल्याण व शिक्षा-स्वास्थ्य & WASH नीति अपनाना
- रोजगार उत्पादन & कौशल निर्माण [शहरी मनरेगा व PMKVY]
- श्रम कोड को व्यावहारिक लागू करना
- न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण व सार्वभौमिक बेसिक इनकम हेतु कार्य करना

Scanned with OKEN Scanner

Q6. What are the key features of foreign Trade polity 2023 of India? Critically Examine the significance in the context of booting India's International Trade and Economy. 250 words

वैश्विक निर्यात में भारत की कुल हिस्सेदारी मात्र 1.7% है जो कि वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने हेतु अपर्याप्त है। इसीलिए नई ~~का~~ विदेश व्यापार नीति 2023 लायी गई।

मुख्य विशेषताएं

↳ 2030 तक कुल व्यापार $2 Tr तक करना

↳ चार प्रमुख स्तंभ –
- छूट [शुल्क, टैक्स]
- सहयोग [ब्रांडिंग, समूह]
- EoDB [विनियामक भूमिका में कमी]
- उभरते क्षेत्र को बढ़ावा [ई-कॉमर्स, फार्मा]

↳ डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब (DEH) को बढ़ावा
↳ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट

- निर्यात एक्सीलेंस टाउन्स (TEE)
  - स्थानीय हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट आदि को वैश्विक पहचान
- पूंजीगत वस्तुओं को निर्यात छूट (EPCG)
  - अवसंरचनात्मक ढांचा मजबूती
- रैंकिंग आधारित निर्यात इकाईयाँ
- नवीन व प्रभावी संधारणीय तकनीकी निर्यात प्रोत्साहन
  - → तकनीकी टैक्सटाइल्स (PM MITRA)
  - → हरित हाइड्रोजन व ऊर्जा
  - → ई-व्हीकल्स व हाइब्रिड फ्यूल सेल निर्माण
- वैश्विक विनिर्माण हब बनना
  - चीन +1 के रूप में पहचान
- MSMEs व कुटीर उद्योगों हेतु विवाद निपटान नीति → 'विवाद से विश्वास'

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व अर्थव्यवस्था हेतु महत्व

- निर्यात केन्द्र की पहचान संभव
- स्थानीय इकाइयों को प्रोत्साहन द्वारा बढ़ावा
- स्थानीय वस्तुओं को ग्लोबल पहचान (GI Tag व अन्य लाभ)
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक के रूप उभरना

लेकिन अवसंरचना ढांचा मजबूत नहीं

EODB में अभी भी समस्याएं व फंडिंग अपर्याप्तता

गुणवत्ता व WTO आदि में सब्सिडी (RoDTEP) का विरोध

चीन, USA, जापान आदि द्वारा ग्लोबल सप्लाई चैन पर कब्जा

जरूरत → गतिशक्ति व बैंकिंग सुधारों पर जोर

↳ EODB को प्रोत्साहन [बजट 2023-24 → 1400 पुराने नियम समाप्त किए]

↳ सिंगल विंडो सिस्टम व EFA में कुछ छूट

इस प्रकार वैश्विक सप्लाई के रूप में हब बनने हेतु सरकार के साथ-साथ व्यावसायिक इकोसिस्टम निर्माण की भी जरूरत पड़ेगी।

Scanned with OKEN Scanner

Q7. While the GST's journey has given its stakeholders some causes to celebrate, it has also given moments of worry. In the context of the above statement critically examine the GST regime and significance of GST Council. 250 words

GST का दूसरा अर्थ एक देश - एक कर - एक बाजार है। इसका आगमन 101वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा हुआ जिसने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में कई बदलाव किए।

GST की सफलताएं

- अप्रत्यक्ष कर नीति का सरलीकरण
- कैसकेडिंग इफैक्ट व आंतरिक करों की समाप्ति
- अनु. 279A के तहत GST परिषद द्वारा सामूहिक फैसले ⇒ सहकारी संघवाद
- EoDB व क्षेत्रीय असमानता को पाटने में सफलता
- पेपरलेस व सीमलेस कर अदायगी ↳ GSTN पोर्टल द्वारा।

Scanned with OKEN Scanner

↳ सरकार को उच्च कर राजस्व प्राप्ति
↳ 2022 में रिकॉर्ड 116 Lcr ₹

परन्तु समस्याएं

↳ GST मुआवजा राशि की समय पर अदायगी नहीं [TN द्वारा SC तक में जाना]

↳ केन्द्र द्वारा सेस व सरचार्ज का अधिक प्रयोग ⇒ राज्यों के कर राजस्व में कमी

↳ GST परिषद द्वारा लिए गए फैसले बाध्यकारी अथवा सिफारिशी पर द्वन्द्व [SC द्वारा हाल में बाध्यकारी माना नहीं परन्तु GST Act 2016 के अनुसार]

↳ पेट्रोल, डीजल, शराब आदि कई उत्पादों का GST Regime से बाहर होना

इस प्रकार उपरोक्त समस्याओं के सामूहिक हल हेतु GST परिषद की

महत्व बढ़ा है

↳ सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व
↳ राज्यों को 2/3 वोटिंग अधिकार देकर संघवाद को मजबूती
↳ GST Regime को निश्चित करने वाली एकमात्र संस्था
↳ केन्द्र सरकार की कर शक्तियों को संतुलित रखने व संवाद मंच प्रणाली

चुनौती → पेट्रोलियम उत्पादों को एक नई GST स्लैब [थोड़ी उच्च] बनाकर GST दायरे में लाना
↳ GST परिषद निर्णयों को बाध्यकारी बनाना
↳ GSTN पोर्टल पर समयपूर्ण फाइलिंग में छोटे-कुटीर व्यवसायों को छूट [GST Composition Scheme]

इस प्रकार एक देश का एक कर तभी एकता व सफलता प्राप्त करेगा जब समय के साथ बदलाव व आपसी केन्द्र-राज्य सद्भावना होगी।

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q8. Discuss the factors that impacted the cropping pattern in India. What changes in the cropping pattern in you would suggest to make Indian farming system a viable sector in India? Can going back of the millet-based agriculture be a solution? Substantiate your view. 150 words

भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 62% क्षेत्र पर फसल बुवाई होती है तथा लगभग 55% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है।

फसल प्रारूप - प्रभावित कारक

↳ भौगोलिक अवस्थिति
↳ पश्चिमी क्षेत्र शुष्क अत: बाजरा जबकि दक्षिणी क्षेत्र में जल अधिकता के कारण चावल।

↳ पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यत: काजू, केसर व चाय-कॉफी जबकि मैदानी क्षेत्र में गेहूँ, जूट, ज्वार।

↳ मृदा रूप - काली कपास हेतु उचित जबकि लाल-पीली मूंगफली।

↳ उद्योग अवस्थिति — महाराष्ट्र - गुजरात में वाणिज्यिक फसलें ज्यादा जबकि यूपी - बिहार आदि में खाद्यान्न।

↳ MSP कारक — सरकार द्वारा ज्यादा MSP वाली फसल ज्यादा उगाना ⇒ लाभ प्राप्ति

परन्तु अभी भी कृषि क्षेत्र की वार्षिक विकास लगभग 3.5% तक ही है।

फसल पैटर्न परिवर्तन की जरूरत

↳ जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिरोधी फसल ⇒ ज्वार, बाजरा आदि

↳ पंजाब - हरियाणा क्षेत्रों में चावल कृषि को हतोत्साहित करना ⇒ गेहूं व अन्य फसल पैदावार अधिक & मरुस्थलीकरण।

↳ वाणिज्यिक फसलों पर भी ध्यान देना ⇒ जूट, कपास, काजू आदि पर

↳ सिंचाई प्रक्रिया में माइक्रो इरिगेशन व स्प्रिंकलर का प्रयोग जरूरी

↳ बीजों का समपरख में प्रतिस्थान व कीटनाशकों का कम उपयोग (5:2:1 में)

↳ कृषि क्षेत्रों को बैकवर्ड – फॉरवर्ड लिंकेज

मोटा अनाज की ओर लौटना

↳ मरुस्थलीकरण व घटते भू-जलस्तर को रोकना

↳ उच्च पोषक तत्व – फाइबर, आयरन आदि के कारण खाद्य सुरक्षा व पोषण

↳ भारत में बड़ा क्षेत्र मोटा अनाज हेतु अनुकूल

↳ प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन व ग्लूटेन की अभाव ⇒ स्वास्थ्य, मधुमेह, बी.पी. आदि में उपयोगी

इस प्रकार बदलते जलवायविक व सामाजिक – आर्थिक पैटर्न के अनुसार हमारी कृषि को प्रतिरोधी व संधारणीयता के साथ समावेशी बनाना समय की मांग है।

Q9. Discuss the positives and challenges associated with minimum support price (MSP) till now. Do you think that MSP regime has rescued the farmers from the low-income trap? Justify your views along with further suggestions 250 words

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सरकार द्वारा फसल बुवाई से पूर्व फसलों की न्यूनतम कीमत घोषणा है, जिसपर किसान अपनी फसल को बाजार में बेच सकते हैं।

वर्तमान में यह $\frac{(A2+FL)\times 3}{2}$ सूत्र के आधार पर 23 फसलों हेतु घोषणा

सकारात्मक

- किसानों को डिस्ट्रेस सेल बचाव
- प्रतिवर्ष बाजार मांग-आपूर्ति परिवर्तन के कारण कीमत परिवर्तन से बचाव ⇒ कोबवेब सहित
- फसल प्रारूपण - विशेष फसल की बुवाई प्रोत्साहन निर्धारण
- खाद्य सुरक्षा → NFSA-2013 की पूर्ति

↳ किसानों की सामाजिक सुरक्षा व बिचौलियों से छुटकारा।

नकारात्मक

↳ केवल कुल फसल उत्पादन का 6% की प्रोक्योरमेंट।

↳ मुख्यतः उच्च गेहूँ - चावल उत्पादन राज्यों से ही FCI खरीदी।

↳ FCI द्वारा बजटेतर संसाधन (Extra Budgetary Resources) का प्रयोग कर क्षमता से अधिक खरीदी (3.5 गुना)

↳ APMC मंडियों में मार्केट समिति व सर्विस लेवी आदि द्वारा किसान शोषण।

क्या MSP ने किसानों को कम कीमत जाल से बचाया

हाँ	नहीं
→ फसल की पूर्व कीमत निर्धारण → आश्वस्त व कम कीमत पर नहीं बेचना।	→ केवल कुछ क्षेत्रों को लाभ → PB, HR, UP, MP, MH व दक्षिणी राज्य।

→ बाजार खरीदारों हेतु बेंचमार्क रेट की तरह

→ निश्चित फसल का उत्पादन व FCI द्वारा जिला स्तर पर आसान प्रोक्योरमेंट

→ बड़े किसानों के साथ छोटे किसान भी आसानी से फसल बेचकर ⇒ धन प्राप्ति व अगली फसल की उचित समय पर तैयारी।

→ गेहूँ - चावल खरीदी पर ज्यादा जोर + अन्य फसलें काफी कम

→ FCI द्वारा गुणवत्ता आधार पर खरीदारी करने से मनाही

→ स्थानीय स्तर पर बिचौलियों के साथ कार्टेल निर्माण

→ FCI खरीदी केवल जिला स्तर पर ⇒ पहुँच से दूर व परिवहन लागत↑

सुझाव → FCI का स्थानीय स्तर पर प्रोक्योर (GrAM व PrAM आदि द्वारा)
↳ eNAM व कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग कॉन्सेप्ट लागू
↳ APLM Act 2016 में मार्केट समिति व अन्य संस्थागत सुधार अत्यावश्यक
↳ FCI सुविधाओं की आउटसोर्सिंग (संसदीय स्थायी समिति)

इस प्रकार खाद्य - किसान सुरक्षा की बेहतर सुरक्षा बेहतर नीति क्रियान्वयन द्वारा ही होगी

10. Discuss the scope and significance of food processing industry in India. Also, elaborate upon the upstream and downstream requirements of the food processing industry in India. 250 words

फूड प्रोसेसिंग मैनुअल के अनुसार यह सेक्टर GDP में ~8% का योगदान दे रहा है तथा कुल रोजगार का 12.7% इसी में संलग्न है।

खाद्य प्रसंस्करण का महत्व

- निर्यात हिस्सेदारी ~13.7% [वार्षिक बजट]
- कृषि क्षेत्र व सेवा क्षेत्र के बीच सेतु का कार्य
- बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज
- खाद्य बर्बादी को कम करना [94MT/yr ASSOCHAM]
- अनाज को कीमती व बेहतर उत्पाद में बदलना
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकता ⇒ ड्रिवल डिवाइड को पाटना।

↳ महंगाई व मांग - आपूर्ति शृंखला का बेहतर प्रबंधन।

अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम जरूरतें

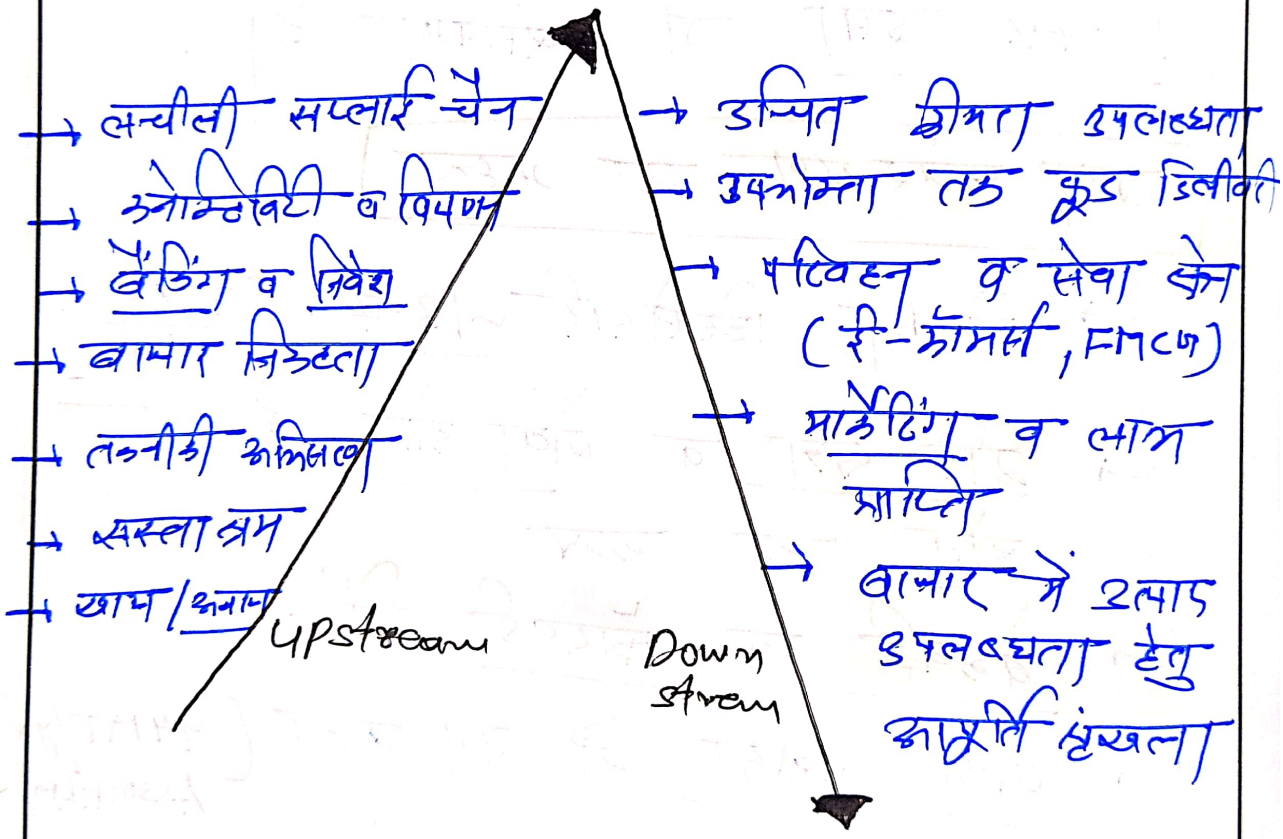

इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग न केवल किसानों व अन्नदाता आदि के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित

कर रहा है बल्कि आर्थिक विकास
हेतु पुल की तरह कार्य कर रहा है।

Scanned with OKEN Scanner